महत्वपूर्ण एवं खास

डिम्पल साहू रियो डी जनेरियो में मिस टीन ग्लोबल ब्यूटी इंटरनेशनल में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व

रायपुर (आरएनएस)। किरंदुल दंतेवाड़ा में जन्मी डिम्पल साहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्राजील के रियोडी जनेरियो में मिस टीन ग्लोबल ब्यूटी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका मुकाबल 30 अन्य देशों के प्रतिभागियों के साथ होगा। हॉल ही में उन्होंने जयपुर में आयोजित मिस सुपर मॉडल प्रतियोगिता 2023 एवं मिस टीन इंडिया 2023 में जूरी की हैसियत से निर्णायक बोर्ड में शामिल हुई। उक्त जानकारी उन्होंने प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में दी।

अग्निवीर भर्ती रैली : 28 मार्च से 3 अप्रैल 2024 तक होगी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के प्रेस विज्ञप्ति अनुसार भारतीय वायुसेना में एयरमेन (श्रेणी-गैर तकनीकी पद) मेडिकल असिस्टेंट में 12 वीं पास तथा मेडिकल असिस्टेंट (डिप्लोमा इन फार्मेसी, बीएसी इन फार्मेसी) पद पर केवल पुरुष आवेदकों हेतु नियमित भर्ती की जा रही है। इस संबंध में भारतीय वायुसेना द्वारा 28 मार्च से 3 अप्रैल 2024 सुबह 6 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में रैली का आयोजन किया जा रहा है। उक्त भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए या लक्ष्य संस्थान मंदिर के सामने मेन रोड दंतेवाड़ा में संपर्क (मोबाईल नं. 62651-52991) से किया जा सकता है।

रेत के अवैध खनन के मुद्दे पर सदन हुआ गरम

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। इस गंभीर मुद्दे पर आज सदन गरमाया। सदन में पामगढ़ के कांग्रेस विधायक ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया। इसके बाद धरमजीत सिंह ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि विभागीय मंत्री स्वयं हवाई सर्वे कर लें, नदी में उन्होंने सैकड़ों वाहनें रेत के अवैध खनन में लगे हुए नजर आ जाएंगे। सदन में विधायक धरमजीत सिंह ने मंत्री को हेलीकॉप्टर से सर्वे करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। सदस्य ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है, घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। जुर्माने के प्रावधान से कुछ फर्क नहीं पडऩे वाला है। सदस्य के इस मांग पर मंत्री ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश दिए हैं। गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन हैं। आज कई अहम् मुद्दों पर मंत्रियों से सवाल-जवाब किये जायेंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष खुद भी सरकार के मंत्रियों को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं।

सीबीआई को मिली जांच की अनुमति: डीएसपीई अधिनियम के तहत ब्यूरो करेगी जांच

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को राज्य में कार्यवाही करने की दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। अब सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने एक मामले में जांच की अनुमति जारी की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को राज्य में एक मामले की जांच की अनुमति दे दी है। भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की जांच सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीआई) अधिनियम के तहत जांच करेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने नोटिफि केशन जारी कर दिया है। बात दें कि सीबीआई की स्थापना डीएसपीआई एक्ट के तहत की गई है और ब्यूरो इसी एक्ट के तहत कार्यवाही करती है। सीबीआई को जांच की अनुमति सीबीआई को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भिलाई आईआईटी के स्थाई परिसर को किया राष्ट्र को समर्पित : 400 एकड़ में विकसित हो रहा है भिलाई का आईआईटी कैंपस

❒ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े, प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार

❒ प्रधानमंत्री ने कवर्धा और कुरुद केन्द्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवनों का किया ऑनलाइन लोकार्पण

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्थाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जम्मू में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के साथ ही कुरुद और कवर्धा में केन्द्रीय विद्यालय के नए बने भवनों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भिलाई आईआईटी से ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने भिलाई के उच्च तकनीकी राष्ट्रीय संस्थान आईआईटी के स्थाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। करीब 400 एकड़ में संस्थान का कैंपस विकसित किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल, विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा और ललित चन्द्राकर, पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, रमशीला साहू, भिलाई आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के. वेंकटरमनन और निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश भी लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भिलाई आईआईटी में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू से देश के लिए 32 हजार करोड़ रुपए की 220 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें छत्तीसगढ़ की भी तीन शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आईआईटी भिलाई परिवार को सर्वसुविधायुक्त स्थाई कैंपस मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आईआईटी उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा।

सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों भिलाई आईआईटी को राष्ट्र को समर्पित करते देखने के साक्षी हैं। प्रधानमंत्री ने आज देश भर में अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। देश के युवाओं को आज बड़ी सौगात मिली है। भिलाई आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के. वेंकटरमनन और निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व विधायक लाभचंद बाफना और भिलाई आईआईटी के रजिस्ट्रार सेवानिवृत्त विंग कमांडर डॉ. जयेश चन्द्र एस. पई सहित अनेक जनप्रतिनिधि, आईआईटी के प्राध्यापक और छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

एक हजार से ज्यादा छात्र अध्ययनरत, 2016 में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में प्रारंभ हुई थी कक्षाएं, परिसर की कई भवनें छत्तीसगढ़ की नदियों और पहाड़ों के नाम पर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में अभी एक हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग की 11 शाखाओं (Branches) में पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2016 में आईआईटी के अस्थाई परिसर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में कक्षाएं लगना प्रारंभ हुई थीं। अगस्त-2023 से भिलाई स्थित स्थाई परिसर में कक्षाएं लग रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 जून 2018 को भिलाई में आईआईटी परिसर के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद 8 जुलाई 2020 से इसका निर्माण आरंभ हुआ था। आईआईटी भिलाई का परिसर 400 एकड़ में फैला है। आरंभिक रूप से इसके निर्माण के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1090 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत कर परिसर में लेक्चर हाल, सेमिनार रूम, क्लासरूम आदि बनाए हैं। यहां निर्मित कई भवनों के नाम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों और पहाड़ों के नाम पर इंद्रावती, शिवनाथ, कन्हर, मैनपाट, गौरलाटा, सिहावा, पेलमा इत्यादि रखे गए हैं।

विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर शोध करना चाहिए: राज्यपाल

❒ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न

रायपुर । राज्यपाल एवं कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में आज यहां पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर का 27वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एवं मुख्य अतिथि प्रो.(डॉ.) बुद्ध रश्मि मणि उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में प्रख्यात कवि माधव कौशिक को मानद उपाधि, 45 हजार से अधिक विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पी एच डी की डिग्री प्रदान की गई।

राज्यपाल ने डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का प्रयोग, समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए करना चाहिए। राज्यपाल हरिचंदन ने कहा कि विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्र में ऐसे विषयों पर काम करना चाहिए जैसे सामाजिक न्याय, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण आदि जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जिन पर बहुत कुछ शोध किए जाने की आवश्यकता हैं, आज पूरा विश्व ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल्स और नैतिक मूल्यों पर भी बराबरी से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों का वंचित वर्ग के लोगों के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना विकसित भारत में सक्रिय होकर भाग लेना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जागृत होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज यहां काफी संख्या में लड़कियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करते देखना खुशी की बात है। महिलाएँ दुनिया की लगभग आधी आबादी हैं और वे न केवल प्रमुख हितधारक हैं, बल्कि विकास प्रक्रिया की वास्तुकार भी हैं। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह सही अवसरों और वातावरण के साथ सशक्त होने पर महिलाओं की असीमित क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपना अमृत काल मना रहा है। आज भारत की स्थिति विश्व में काफी मजबूत है।

समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ उनके कौशल को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना है। वर्तमान युग में नवाचार, समावेशी शिक्षा, तकनीकी योग्यता और कौशल विकास किसी भी शिक्षा-प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक बन चुके हैं। हमारी सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा को नई पहचान दिलाने हेतु सदैव कृतसंकल्पित रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्वस्तर पर पुर्नस्थापित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शोध पर विशेष जोर देना होगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे शोध किए जाने चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और यह भी लोगो के लिए लाभदायक साबित हो। दीक्षांत भाषण प्रो. डॉ. बुद्ध रश्मि मणि ने दिया।

एक्सपायरी केक बेचने वाली होटल से रेलवे ने वसूला 25 हजार का जुर्माना

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर रेलवे स्टेशन में एक्सपायरी केक बेचने वाली होटल से रेलवे ने 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूल लिया है. ये जुर्माना बिलासपुर से आई टीम ने पिछले दिनों जांच के दौरान लगाया था. वहीं कमर्शियल विभाग के अधिकारियों ने सोपान होटल संचालक को चेतावनी भी दी. सूत्रों के मुताबिक रायपुर रेलवे स्टेशन में एक्सपायरी या नीयर बॉय एक्सपायरी (जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी करीब हो) प्रोडक्ट बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा है. लेकिन रायपुर रेलवे स्टेशन में तैनात कमर्शियल विभाग के अधिकारी जिन्हें इसकी जांच करनी है वो इसकी जांच नहीं करते और ये खेल लंबे समय से चल रहा था. जिसके बाद सूचना बिलासपुर की टीम के पास पहुंची और वे रायपुर कार्रवाई करने पहुंचे थे.

प्रशिक्षण के बाद आईपीएस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा (2020-21 बैच) के अधिकारियों का जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद नवीन पदस्थापना की है. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है. इस सूची में कुल सात आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल हैं. जिनकी नई पोस्टिंग की गई है। जिसमे आकाश कुमार शुक्ला (भापुसे-2021) जिला-रायपुर को नगर पुलिस अधीक्षक, रायगढ़। चिराग जैन (भापुसे-2020)जिला-सरगुजा को नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग।

अमन कुमार रमन कुमार झा (भापुसे- 2021) जिला-बिलासपुर को नगर पुलिस अधीक्षक, रायपुर। रविन्द्र कुमार मीणा (भापुसे 2021) जिला-बस्तर को नगर पुलिस अधीक्षक, कोरबा। रोहित कुमार शाह (भापुसे- 2021)जिला-कोरबा को नगर पुलिस अधीक्षक, सरगुजा।

उदित पुष्कर (भापुसे 2021) जिला-रायगढ़ को नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर।

और उमेश प्रसाद गुप्ता जिला-दुर्ग को नगर पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को स्थानांतरित किया गया है।

धान की सीधी बुआई से 25 % पानी और प्रति हेक्टेयर 6 हजार रूपये लागत में कमी

❒ धान की सीधी बुआई तकनीक पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं कृषक सम्मान समारोह सम्पन्न

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलिपींस एवं बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड के सहयोग से आज यहां धान की सीधी बुवाई तकनीक पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं कृषक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कृषि महाविद्यालय रायपुर के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य कृषकों तक धान की सीधी बुवाई हेतु उन्नत तकनीकी जैसे नई मशीनों से बुवाई, खरपतवार प्रबंधन की नवीन विधियां, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समुचित जल प्रबंधन के माध्यम से संसाधनों का सही उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि धान की सीधी बुआई तकनीक से लगभग 25 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है, प्रति हेक्टेयर लागत में लगभग 6 हजार रूपये की कमी आती है और यह तकनीक पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही मृदा संरक्षण को बढ़ावा देती है।

इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार समन्वयक उड़ीसा डी.एस.आर. इरी प्रोजेक्ट, ने अपने संबोधन में डी.एस.आर. की सक्सेस स्टोरी एवं उड़ीसा में उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बारे में बताया साथ ही बायर क्रॉपसाइंस के वैज्ञानिक एवं अधिकारियों ने भी अपने उद्बोधन में धान की सीधी बुवाई में नए प्रयोग एवं भविष्य में आने वाले नए उत्पाद एवं प्रजातियां जो कि अधिक किसानोपयोगी है के बारे में विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. अजय वर्मा एवं निदेशक प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. एस.एस. टुटेजा उपस्थित थे। डॉ. विवेक त्रिपाठी संचालक अनुसंधान सेवाएं ने अपने उद्बोधन में कृषकों को सीधी बुआई तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग कर इसके अंतर्गत रकबा बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. वर्मा एवं डॉ. टुटेजा ने भी कार्यशाला में अपने विचार रखे।

तकनीकी सत्र में पांच विषय विशेषज्ञों द्वारा उद्बोधन दिया गया जिसमें डॉ. अशोक कुमार, डॉ. एस. बी. वेरुलकर, डॉ. आरके नायक, डॉ. सुधांशु मिश्रा एवं डॉ. संजय द्विवेदी ने डीएसआर के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

छत्तीसगढ़ के किसानों के आय दोगुना करने तकनीकि पहलुओं पर हुई चर्चा

❒ मंत्री नेताम ने केन्द्रीय कृषि एवं जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कृषि विकास और आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा से सौजन्य मुलाकात की।

कृषि मंत्री नेताम ने छत्तीसगढ़ के किसानों की भविष्य की चिन्ता करते हुए उनकी आय दोगुनी करने के लिए केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा से तकनीकि पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। प्रदेश में किसानों को धान के अलावा लघु धान्य फसलों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ में इथेनॉल तैयार करने के लिए मक्का की फसलों की संभावनाओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की।

कृषि मंत्री नेताम के नेतृत्व में अधिकारियों के दल द्वारा केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा और अधिकारियों से भी किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर ड्रोन पद्धति, सामुदायिक वानिकी, लघु उद्योग हेतु छोटे-छोटे यूनिट्स और मैक्नाईजेशन के लिए 1100 करोड़ रूपए के प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री को सौंपा गया। केन्द्रीय मंत्री द्वारा इन प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए आश्वस्त किया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रस्तावों पर सहमति है और जल्द से जल्द अनुमोदित करने हेतु निर्देश किया जाएगा। इन प्रस्तावों के स्वीकृत हो जाने से प्रदेश में मक्का के फसलों को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक वर्ष मक्का के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढऩे की संभावना है, इससे लगभग हर वर्ष 1,45,000 हेक्टेयर मिलेट की खेती कराया जा सकेगा। मुलाकात के दौरान पीएम प्रणाम योजना और नैनो उर्वरक, मैक्नाईजेशन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। मंत्री नेताम ने इस दौरान केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा को बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों की उन्नति के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता को किए गए वादों को पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी है। किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा मोदी की गारंटी के अनुरूप अंतर की राशि जल्द प्रदाय किया जाएगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

पीएम आवास के लिए छोटे ट्रैक्टर से मिलेगा नि:शुल्क रेत : ओपी चौधरी

❒ रेत अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आई

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में रेत के अवैध खनन, परिवहन के मुद्दे पर आज विधानसभा में सत्ता पक्ष घिरती नजर आई। विपक्ष के साथ ही कुछ अन्य सदस्यों ने आज प्रदेश में चल रहे रेत के अवैध खनन, परिवहन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मामला उठाते हुए कहा कि अवैध रेत खदान की शिकायत आई है. क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को मशीन से लोडिंग की अनुमानित नहीं है. बिना अनुमति के अगर कहीं खनन चल रहा है तो इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप अभी हेलीकॉप्टर से अभी चलिए, अगर 200 से ज़्यादा पोकलेन उत्खनन करती नहीं मिली तो मैं अपनी विधायिका से इस्तीफ़ा दे दूंगा।

पूर्ववर्ती सरकार ने रेत पर किया बड़ा खेल : धरमजीत सिंह

धर्मजीत सिंह ने पंद्रह दिन तक अभियान चलाने का निवेदन करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है. बेहतर है कि पूर्व की तरह इसका अधिकार पंचायत को दिया जाए. वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग इस पर नज़र रखे हुए है, और उचित कार्यवाही की जा रही है. आसंदी ने मंत्री से कहा कि आप ऐसी कठोर कार्यवाही कीजिए कि नजीर बने. इसके साथ ही मंत्री चौधरी ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

अरपा नदी से रेत के अवैध परिवहन का मामला उठा : भाजपा-कांग्रेस के कई विधायकों ने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में बात रखी. बिलासपुर में अरपा से रेत के अवैध उत्खनन का मामला भी उठा. ग्रामीणों को आ रही परेशानी को लेकर भी उठे सवाल. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत ले जाने की गांव वालों को अनुमति देते हैं? ये बड़ी बात होगी. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि गांव वाले खुद के उपयोग के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए छोटे ट्रेक्टर से रेत नि:शुल्क दिया जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि रेत से तेल निकालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अवैध भंडारण पर भी हो कार्रवाई : रिकेश सेन ने कहा कि खनिज जब्त होता है, तो कहां रखा जाता है? इस पर मंत्री ने कहा कि खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है. फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है. रिकेश सेन ने कहा कि पिछले 5 सालों में रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री चौधरी ने कहा कि जो खनिज जप्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसको वापस लेकर ऑक्शन नहीं करते हैं. खनिज की राशि और पेनाल्टी दोनों लेने के बाद उसे ही खनिज दे दिया जाता है. इस पर रिकेश सेन ने जिला सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर में जितने भी खनिज जप्त हुए हैं, उस पर जांच के साथ शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।